आयकर स्लैब : कोई बदलाव नहीं, मध्य वर्ग को फिर झटका | **पूंजीगत व्यय : 35.4 फीसदी ज्यादा 7.5 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार** | **स्टार्टअप व एमएसएमई को राहत एक साल बढ़ाई**

डिजिटल मुद्रा के रथ पर अर्थव्यवस्था क्रिप्टोकरेंसी की एहतियाती खुराक भी

टीम अमर उजाला

नई दिल्ली। आजादी के 75वें साल से शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ता भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल रहा है। संसद में मोदी सरकार का नौवां बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल डिजिटल मुद्रा लाने का एलान किया। क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार की मुहर भी लग गई। इससे कमाई पर 30 फीसदी कर और राशि हस्तांतरण पर एक फीसदी टीडीएस लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए बैटरी अदला-बदली नीति और प्रौद्योगिकी व स्टार्टअप माहौल बनाने के लिए इसी साल से 5जी शुरू किया जाएगा।

सीतारमण ने अगले 25 साल के लिए देश के विकास का दृष्टिकोण पेश किया। महामारी की तीसरी लहर के बीच पिछले बजट के मुकाबले निवेश और पूंजीगत खर्च बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में 9.27 फीसदी विकास दर की उम्मीद जताई। राजमार्ग विस्तार से लेकर किफायती आवास जैसी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के बावजूद आम करदाताओं को कोई राहत नहीं दी, लेकिन दावा किया कि सरकारी खर्च बढ़ाने के कारण यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और अनुसूचित जाति-जनजातियों के हित में होगा। निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ने से अगले 12 महीने में 60 लाख नई नौकरियां मिलने का दावा भी किया। उन्होंने कहा, हमने चार प्राथमिकताएं तय की हैं- पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादन वृद्धि व निवेश एवं चौथा, सौर ऊर्जा, ऊर्जा हस्तांतरण और जलवायु अभियान। अगले 25 साल के अमृतकाल के लिए बजट अर्थिकी की नींव मजबूत करेगा। पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने वित्तीय घाटा पिछले साल के 6.9 फीसदी के मुकाबले इस वर्ष जीडीपी के 6.4 फीसदी तक लाने का लक्ष्य है। पूंजीगत खर्च में 35.4 फीसदी ज्यादा यानी सरकार 7.5 लाख करोड़ खर्च करके अर्थव्यवस्था को गति, विकास और रोजगार सृजन का सपना संजोए है।

बुनियादी ढांचे पर फोकस : बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी, 25 हजार किमी तक राजमार्ग निर्माण, नदियों को जोड़ने की योजना और 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने पर खर्च किया जाएगा। पीएम गतिशक्ति में रोड, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्थिक और स्थायी विकास को रफ्तार मिलेगी। 107 लाख करोड़ रुपये की परियोजना में रेल-सड़क सहित 16 मंत्रालय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगे, जिससे एक-दूसरे की परियोजनाओं का पता चलता रहेगा।

60 लाख नए रोजगार उत्पादन प्रोत्साहन योजना के जरिये

30 लाख करोड़ अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता

ब्लॉकचेन भविष्य की तकनीक है। इसके सहारे डिजिटल मुद्रा से सरकार भी क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में दस्तक दे सकती है। निवेशकों के समक्ष सरकारी या गैर सरकारी क्रिप्टोकरेंसी चुनने का विकल्प होगा।

विकास का नया विश्वास...नए अवसर भी

बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानव के लिए यह बजट अनेक नए अवसर बनाएगा। ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा निवेश, ज्यादा विकास और ज्यादा रोजगार की नई संभावना से भरा हुआ है यह बजट। इससे ग्रीन जॉब्स का क्षेत्र भी खुलेगा। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

डिजिटल अर्थव्यवस्था...तकनीक समर्थित विकास

हमारा विजन अगले 25 साल में सूक्ष्म आर्थिक स्तर-समग्र कल्याण पर बल देते हुए व्यापक आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था व फिनटेक, तकनीक समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्ययोजना को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक पूंजी निवेश की मदद से निजी निवेश शुरू करने के प्रभावी चक्र से लोगों को सहायता करना है। - निर्मला सीतारमण, वित्तमंत्री

पांच राज्यों में चुनाव के बीच किसानों का ध्यान

2.37 लाख करोड़

एमएसपी पर गेहूं व धान की खरीद 1.63 करोड़ किसानों को सीधा भुगतान

- गंगा किनारे पांच किमी तक जैविक खेती।
- नाबार्ड कृषि व ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्ट-अप को वित्तीय मदद के लिए बनाएगी मिश्रित पूंजी कोष।
- फसल आकलन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशक व पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन।
- **चालू वित्त वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है...कृषि क्रेडिट लक्ष्य 18 लाख करोड़।**
- **प्रधानमंत्री आवास योजना :** गरीबों के 80 लाख घर बनाने के लिए 48 हजार करोड़ का आवंटन।

फिर निराशा...आयकर स्लैब में बदलाव नहीं

आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही, कर दरों में भी बदलाव नहीं है।

- राज्य कर्मचारियों को एनपीएस में छूट का दायरा 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया।
- अपडेटेड आईटीआर : गड़बड़ी ठीक करने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा।
- दिव्यांगों को टैक्स में छूट।

वित्तमंत्री का तर्क-कर लगाया भी तो नहीं...पीएम नरेंद्र मोदी का पिछली बार आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में लोगों पर कर का बोझ नहीं डालना है। इस बार भी यही आदेश था कि आम आदमी पर टैक्स नहीं बढ़ाना है। इसी पर अमल किया है। - निर्मला सीतारमण

वन क्लास, वन टीवी चैनल : क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा, डिजिटल यूनिवर्सिटी

पीएम ई-विद्या के तहत संचालित 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए और विस्तार मिलेगा। चैनलों की संख्या 12 से बढ़ाकर 200 होगी, ताकि विद्यार्थी महामारी में हुए नुकसान की भरपाई कर पाएं। स्थानीय भाषा में होगी पढ़ाई।

- विश्वस्तरीय डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
- युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिये स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा।

एमएसएमई : 2 लाख करोड़ अतिरिक्त कर्ज

एमएसएमई को 5 साल में 6000 करोड़ दिए जाएंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की अंतिम तिथि बढ़ाकर 2023 तक की।

- **ईसीएलजीएस :** 50 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये किया दायरा। इससे छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। 130 लाख से अधिक एमएसएमई को ऋण दिए।
- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को लिंक किया जाएगा।

स्टार्टअप : कर छूट एक साल बढ़ी

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2022 के बीच शुरू स्टार्टअप कर लाभ योजना के लिए पात्र थे। पात्रता 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई। ऐसे स्टार्टअप दस साल की कुल समय सीमा में तीन साल के लाभ पर 100% कर छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

सीमा शुल्क में छूट : चमड़ा, कपड़ा, जूते-चप्पल, मेंथा ऑयल, मोबाइल फोन चार्जर, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, विदेश से आने वाली मशीनें और रत्न एवं आभूषण। **सस्ता**

बिना मिलावट वाले जैव ईंधन, आयातित छाते। कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट खत्म। आर्टिफिशियल आभूषण पर कर बढ़ा। **महंगा**

बिना इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर प्रति लीटर 2 रुपये टैक्स

एक अक्तूबर से बिना इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर प्रति लीटर दो रुपये का उत्पाद शुल्क लगेगा। देश में इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने और वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार ने कड़ाई की है। इथेनॉल मिश्रित ईंधन का प्रयोग बढ़ने का सीधा लाभ किसानों व चीनी मिलों को होगा।

विपक्ष को नहीं आया रास : राहुल बोले- युवाओं का भविष्य नजरअंदाज

बजट में वेतनभोगी, मध्य वर्ग, गरीबों, युवाओं, किसान और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। देश में निराशा है। सरकार ने युवाओं के भविष्य को नजरअंदाज किया। -राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

यह बजट 'पेगासस स्पिन बजट' है। इसमें देश के आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है। सरकार बड़े शब्दों में खो गई है जिसका कोई मतलब नहीं। -ममता बनर्जी, सीएम, पश्चिम बंगाल

मानसिक सेहत के सरोकार

मानसिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू होगा। उत्कृष्टता वाले 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क शामिल होगा। निम्हांस को नोडल केंद्र के रूप में बनाया जाएगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर कारोबारी खर्च नहीं

सीतारमण ने साफ किया कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर को व्यवसाय व्यय के रूप में अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा, आयकर व्यवसाय आय की गणना के लिए अनुमति प्राप्त व्यय नहीं है। इसमें कर के साथ अधिभार शामिल हैं। 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' विशिष्ट सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के लिए करदाता पर अतिरिक्त अधिभार के रूप में लागू किया गया है।

5-जी नेटवर्क भी इसी साल

उत्पादन प्रोत्साहन योजना के रूप में एक मजबूत इको-सिस्टम बनाने के लिए डिजाइन।

ई-पासपोर्ट

एंबेडेड चिप और भावी तकनीक वाले ई-पासपोर्ट इसी साल से मिलेंगे

ई-पासपोर्ट व्यक्ति के पहचान सत्यापन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करेगा।

39.45 लाख करोड़

2022-23 में अनुमानित व्यय

22.84 लाख करोड़ रुपये उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां

9.2% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान

वर्तमान वित्त वर्ष का गणित

- बजट अनुमान : 34.83 लाख करोड़
- संशोधित अनुमान : 37.70 लाख करोड़
- राजकोषीय घाटा : जीडीपी का 6.9%

आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र

5.25 लाख करोड़ का प्रावधान

- रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपये किया। सैन्य साजो-सामान के निर्माण में पूंजीगत व्यय के लिए 1,52,369 करोड़ रुपये अतिरिक्त रखे हैं।
- पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए होगा, जो पहले 58% था।
- पूंजीगत व्यय के लिए अलग से 1,52,369 करोड़ रुपये से हथियार, विमान, युद्धपोत खरीदे जाएंगे। पेंशन के लिए 1.19 करोड़ और 20,100 करोड़ रक्षा मंत्रालय के लिए अलग से प्रावधान।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ आवंटित

19 साल पुरानी केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1,400 करोड़ रुपये आवंटित। यूपी के बुंदेलखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक को मिलेगा फायदा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा।

बजट की बारीकियां...अमर उजाला के विशेषज्ञों की नजर से समझिए

राजीव कुमार (उपाध्यक्ष, नीति आयोग) | सीएम वासुदेव (पूर्व वित्त सचिव) | मेघनाद देसाई (अर्थशास्त्री) | अजय बग्गा (अर्थशास्त्री) | मोहन दास पई (पूर्व निदेशक, इन्फोसिस) | निरंकार सिंह (कृषि विशेषज्ञ) | नारायण कृष्णमूर्ति (अर्थशास्त्री) | डॉ. चंद्रकांत लहारिया (जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ) | अनिल स्वरूप (पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव) | डॉ. शरद कोहली (अर्थशास्त्री)

अंदर खास

डिजिटल इकनॉमी	खेती-किसानी
आयकर	सेहत-शिक्षा
उद्योग-कारोबार	परिवहन
अर्थव्यवस्था	सियासत
बैंकिंग	प्रवाह

पर्यटन : आठ रोपवे की सौगात

16.42% बजट बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपये। अवसंरचना विकास के लिए 1644 करोड़ और धार्मिक व मनोहर विरासत के लिए 235 करोड़ रुपये। पहाड़ी राज्यों में 60 किमी के आठ रोपवे इसी साल।

रेलवे : किफायती ट्रेनें, ढुलाई के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद

रेल मंत्रालय को 1,40,367 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछली बार से 20,311 करोड़ अधिक है। तीन साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण होगा। रेल क्षेत्र 'एक स्टेशन एक उत्पाद' विकसित होगा, जिससे स्थानीय उत्पादों की ढुलाई का लाभ मिलेगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमियों के लिए नए उत्पाद और सेवाएं शुरू करेगा।